गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 283
दि. 14.02.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पीएम श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 व 2 के उद्घाटन के अवसर पर समारोह को संबोधित किया

कहा कि यहाँ लिए जाने वाले निर्णय अब किसी सम्राट की सोच को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे

भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया है: प्रधानमंत्री

विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए यह अनिवार्य है कि भारत औपनिवेशिक मानसिकता के हर अंश को त्याग दे: प्रधानमंत्री

रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग करना केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह सत्ता की मानसिकता को सेवा के भाव में बदलने का एक प्रयास था: प्रधानमंत्री

नए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है; सेवा, या सेवा का भाव, भारत की आत्मा है, यही भारत की पहचान है: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 एवं 2 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी एक नए इतिहास के निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि विक्रम संवत 2082, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, 24 माघ, शक संवत 1947, जो वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 13 फरवरी 2026 है, यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरूआत का गवाह बना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शास्त्रों में विजया एकादशी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस दिन लिया गया संकल्प सदैव विजय की ओर ले जाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत के संकल्प के साथ, हम सभी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस लक्ष्य में विजय प्राप्त करने के लिए दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ और इन नए भवनों के लिए पीएमओ टीम, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों सहित सभी को बधाई दी। उन्होंने इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियरों और श्रमिक साथियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक

जैसे भवनों से बनाई गईं। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि इन इमारतों का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीकों के रूप में किया गया था, जिनका उद्देश्य भारत को सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखना था।

श्री मोदी ने स्मरण किया कि कोलकाता कभी देश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान वह ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों का एक सशक्त केंद्र बन गया था। इसी कारण, 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि इसके पश्चात, औपनिवेशिक शासन की आवश्यकताओं और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया कि जब रायसीना हिल्स पर इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब तत्कालीन वायसराय ने कहा था कि ये नई संरचनाएँ ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बनाई गई हैं— अर्थात, वे गुलाम भारत की धरती पर ब्रिटेन के राजा की सोच को थोपने का एक माध्यम थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रायसीना हिल्स का चयन इसलिए किया गया था ताकि ये इमारतें अन्य सभी से ऊपर रहें और कोई भी इनके बराबर खड़ा न हो सके। श्री मोदी ने इसकी तुलना सेवा तीर्थ परिसर से करते हुए कहा कि यह किसी पहाड़ी पर नहीं, बल्कि सीधे धरातल से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि जहाँ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण औपनिवेशिक मानसिकता को लागू करने के लिए किया गया था, वहीं आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यहाँ लिए जाने वाले निर्णय अब किसी सम्राट की सोच को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने की नींव बनेंगे। इसी भावना के साथ, प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन को भारत की जनता को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का पहला क्वार्टर अब पूरा हो चुका है और यह आवश्यक है कि विकसित भारत का विजन न केवल नीतियों और योजनाओं में, बल्कि कार्यस्थलों और भवनों में भी प्रतिबिंबित हो।

'हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, सपा को पूजना है तो पूजे', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और मयार्दा का पालन जरूरी है. साथ ही उन्होंने वाराणसी लाठीचार्ज और एफआईआर पर सवाल उठाए. योगी ने कहा कि साढ़े चार करोड़ श्रद्धालुओं के बीच एग्जिट गेट से अंदर जाने की कोशिश भगदड़ करा सकती है. सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता

और कोई भी हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि मयार्दाओं का पालन सभी को करना होगा. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर वह शंकराचार्य थे तो वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों किया गया था और एफआईआर क्यों दर्ज हुई थी. उन्होंने कहा कि नैतिकता की बात करने वालों को पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए.

सीएम योगी ने कहा कि जहां साढ़े चार करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हों, वहां व्यवस्था और सुरक्षा सर्वोपरि है. साथ ही उन्होंने बताया कि स्नान के बाद श्रद्धालु जिस एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हों, उसी मार्ग से किसी को अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इस तरह का कदम एक नई भगदड़ को जन्म दे सकता है और श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है.

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और ब्रह्म कुमारी के

राष्ट्रव्यापी अभियान 'सशक्त भारत के लिए कर्मयोग' अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रपति ने गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती समारोह का भी शुभारंभ किया।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि संतुलित और समग्र विकास के लिए भौतिक प्रगति के साथ ही नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का समेकन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति समृद्धि को बढ़ावा देती है और तकनीकी प्रगति नवाचार, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है।

प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को बधाई दी; द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की उल्लेखनीय जीत

पर पार्टी के नेता श्री तारिक रहमान से बात की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत में, बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के प्रयास में श्री रहमान को अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश घनिष्ठ पड़ोसी देश हैं और उनके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले- हर एफटीए और समझौता राष्ट्रहित में

हमारी प्रमुख फसलें, डेयरी और पोल्ट्री पूरी तरह संरक्षित- श्री शिवराज सिंह

विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल रखी है, अफवाहों का बाजार फैलाते हैं- श्री चौहान

क्लफक्क के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से बोले शिवराज सिंह- आप केवल डिग्रीधारी नहीं, भविष्य के कृषि-नेता हैं

जिंदगी केवल मौज-मस्ती के लिए नहीं, उद्देश्यपूर्ण जीवन और बड़े लक्ष्य के लिए है- श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)। हितों पर चोट करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ संदेश दिया कि भारत की हर ट्रेड डील

और ऋअ में न तो खेत बिके हैं, न किसान, बल्कि देश की कृषि की रीढ़ को और मजबूत किया गया है। उन्होंने दो टूक कहा कि जो लोग किसानों के नाम पर भय और अफवाह का कारोबार चला रहे हैं, उनकी सारी कथित राजनीति झूठ के सहारे खड़ी है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के किसानों के हित ह्लपूरी तरह सुरक्षितह्व हैं और रहेंगे।

ट्रेड डील में किसानों का हित सर्वोपरि

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली के 64वें दीक्षांत समारोह में अपने उद्बोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल के सभी मुक्त व्यापार समझौतों (ऋअ) और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर उठाए जा रहे सवालों पर स्पष्ट, तथ्यात्मक और सख्त राजनीतिक जवाब दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने सोनीपत स्टार्टअप समिट 4.0 में भाग लिया, उन्होंने डीप-टेक, नवाचार और युवा नेतृत्व वाले औद्योगिक विकास के महत्व पर प्रकाश डाला

श्रीमती खडसे ने केंद्रीय बजट 2026 में खेल सामग्री विनिर्माण संबंधी प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अवसरों पर प्रकाश डाला

(जीएनएस)।

युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने आईआईटी दिल्ली टेक्नोपार्क में आयोजित सोनीपत स्टार्टअप समिट 4.0 में भाग लिया और नवाचार आधारित विकास तथा युवा-संचालित औद्योगिक परिवर्तन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

श्रीमती खडसे ने नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, छात्रों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अनुसंधान, पूंजी निवेश और वैश्विक विस्तार क्षमता से प्रेरित एक निर्णायक गहन प्रौद्योगिकी चरण में प्रवेश कर रहा है। "उद्योग त्वरण संस्करण" विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शोधकताओं, कॉरपोरेट्स और सरकारी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाया गया ताकि प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम विकास को गति दी जा सके।

श्रीमती खडसे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आत्मनिर्भर और नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है।

उन्होंने बताया कि यह शिखर सम्मेलन रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी और कृषि प्रौद्योगिकी सहित उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है। हरियाणा एनसीआर औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत द्वितीय और तृतीय श्रेणी के क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे क्षेत्रीय उद्यमिता राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ सके।

सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे अनुकूल वातावरण पर श्रीमती खडसे ने कहा कि नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन, स्टार्टअप इंडिया और सार्वजनिक-निजी त्वरण मंच जैसी पहलों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन सुविधाएं, मार्गदर्शन और बाजार संपर्क प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट 2026 ने अनुसंधान एवं विकास, गहन तकनीकी नवाचार, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए विस्तारित ऋण गारंटी और हरित विकास पहलों के लिए समर्थन को और मजबूत किया है।

प्रमुख इनक्यूबेशन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थानों और वैश्विक कंपनियों द्वारा समर्थित इस शिखर सम्मेलन ने सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक सशक्त मॉडल प्रदर्शित किया। यह युवा उद्यमियों को बौद्धिक संपदा, वित्तपोषण मार्ग, नियामक ढांचे और उत्पाद-बाजार संरेखण पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

श्रीमती खड़से ने खेल विज्ञान और विनिर्माण नवाचार के बढ़ते अभिसरण पर कहा कि खेल विश्लेषण, पहनने योग्य तकनीक, बायोमैकेनिक्स, रिकवरी विज्ञान और एआई-संचालित प्रदर्शन निगरानी जैसे क्षेत्र भारत में खेल-केंद्रित स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं।

सरकार की युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए श्रीमती खडसे ने कहा कि भारत के युवा नवप्रवर्तक न केवल स्टार्टअप बना रहे हैं बल्कि औद्योगिक क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, तकनीकी स्वतंत्रता को बढ़ा रहे हैं

एनसीएलटी के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामलिंगम सुधाकर अपने पद से कार्यमुक्त हुए

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामलिंगम सुधाकर ने आज, 13 फरवरी 2026 को न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में एक विशिष्ट कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से कार्यमुक्त हो गए। उन्होंने नवंबर 2021 में न्यायाधिकरण में कार्यभार संभाला था। अपने चार वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर ने संस्था को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया और कॉरपोरेट तथा दिवालियापन मामलों में न्याय प्रदान करने में सार्थक योगदान दिया। उनका नेतृत्व परिश्रम, सत्यनिष्ठा और न्यायिक उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित था। न्यायाधिकरण के सदस्यों और एनसीएलटी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी हितधारकों के सामूहिक सहयोग के कारण मामलों के निपटारे की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय कार्यक्रम ने ब्रिक्स देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया, एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

(जीएनएस)।

विदेश मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के सहयोग से, भारत की अध्यक्षता में 9-10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की पहली बैठक का सफल समापन करने के बाद, 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी (एवसीएम एवं एचकेए) में ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं के लिए एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला तथा कला, संगीत एवं व्यंजन सहित जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करना था।

इस अवसर पर ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इंडोनेशिया के शेरपाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के राजदूतों और लगभग 30 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

भारत के ब्रिक्स शेरपा (आर्थिक संबंध सचिव) ने भारत के ब्रिक्स सूस शेरपा (बहुपक्षीय आर्थिक संबंध संयुक्त सचिव) के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी की। प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य मंत्रालय, डीपीआईआईटी और राजस्व विभाग के सचिव, विदेश मंत्रालय के 30 अधिकारी और राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय के अधिकारी भी शामिल थे।+

प्रधानमंत्री ने 'नागरिकदेवो भव' की भावना से प्रेरित होकर 'सेवा तीर्थ' राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'सेवा तीर्थ' कर्तव्य, करुणा और 'इंडिया फर्स्ट' (भारत प्रथम) के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत की जनता की सेवा करने के अपने अटूट संकल्प को दोहराते हुए और 'नागरिकदेवो भव' की पावन भावना को इसकी मार्गदर्शक शक्ति के रूप में रेखांकित करते हुए, 'सेवा तीर्थ' राष्ट्र को समर्पित किया।

श्री मोदी ने कही कि सेवा तीर्थ का समर्पण जनसेवा और नागरिकों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'सेवा तीर्थ' कर्तव्य, करुणा और 'इंडिया फर्स्ट' (भारत प्रथम) के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्ज्वल और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विद्यमान है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सभी के कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए

प्रेरित करेगा और हर नागरिक की भलाई के लिए समर्पण भाव से आगे बढ़ने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

"भारत की जनता की सेवा करने के अटूट संकल्प के साथ और नागरिकदेवो भव की पावन भावना से प्रेरित होकर, सेवा तीर्थ राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला।

मेरी कामना है कि सेवा तीर्थ सदैव कर्तव्य, करुणा और 'इंडिया फर्स्ट' (भारत प्रथम) के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्ज्वल प्रतीक के रूप में अडिग रहे।

यह आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सर्व-कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहे।"

सम्पादकीय

विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव

संसद में जहां विपक्ष अभी तक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर ही चर्चा हो रही थी, वहीं अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को नोटिस दे दिया है। जहां विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने का नोटिस लोकसभा के महासचिव को दिया और आरोप लगाया कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, वहीं विपक्ष के कई सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए वे सभी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। विपक्ष का यह नोटिस सामान्य और स्वाभाविक लगता है किन्तु सत्तापक्ष के सदस्य निशिकांत दुबे की विशिष्ट प्रस्ताव के लिए दिया गया नोटिस अत्यन्त गंभीर परिस्थिति की तरफ संकेत है। कहने को तो यह नोटिस विशिष्ट प्रस्ताव के लिए है यानि यह विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके पीछे पाटा द्वारा नोटिस दी जाती है। किन्तु संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा और कांग्रोस पाटा के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि अब दोनों एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की संसदीय मर्यादा की परवाह करने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेता यानि लोकसभा के सदस्य को उसकी सदस्यता छीनने के लिए दी गई है विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस। मजे की बात तो यह है कि लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होते ही लोकसभा के सदस्य को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है।

वास्तविकता तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास पारित करना विपक्ष के लिए आसान नहीं है किन्तु यदि भाजपा ने रणनीति के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने का पैसला कर लिया तो सदन में सामान्य बहुमत जुटाना बिल्वुल मुश्किल नहीं है। भाजपा ने यदि यह पैसला कर ही लिया हो कि हम तो अपना यानि स्पीकर का देख लेंगे किन्तु तम्हें नहीं छोड़ेगा। और यह स्थिति राहुल और कांग्रोस दोनों के लिए ही घातक साबित होगी। इसी को कहते हैं 'आ बैल मुझे मार' जो कांग्रोस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है।

यह तो सच है कि यदि लोकसभा में सामान्य बहुमत से निशिकांत दुबे का प्रस्ताव पारित हो गया तो लोकतंत्र के लिए अत्यन्त चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई निति रूप से लोकतंत्र के लिए संवेदनशील मानी जाती है।

मजे की बात तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए दिए गए नोटिस को ही रद्द कराने के लिए भाजपा सक्रिय हो गई है। किन्तु राहुल पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वैसे वह सोरोस फाउण्डेशन, फोर्ड फाउण्डेशन, यूएस एआईडी के साथ मिलकर थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, अमेरिका जाते हैं और किस तरह भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले रहते हैं।

यह सच है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अब लोकसभा तक को नहीं छोड़ा किन्तु यह भी सही है कि कांग्रोस पाटा में से कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आकर सत्तापक्ष से बातचीत करके अविश्वास की खाई समाप्त करने की कोशिश करे। जब कांग्रोस में सत्ता में रहती थी तो दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के संसद भवन स्थित कक्ष में विपक्ष के ज्यादा सदस्यों को देखा जा सकता था क्योंकि वे हर गतिरोध को टालने के लिए सत्तापक्ष के सदस्यों को सहयोग देने का वादा करते थे। यही नहीं गतिरोध समाप्त करने का रास्ता निकालते थे। इसी तरह अटल जी की सरकार में दिवंगत माधव राव सिंधिया और प्रिय रंजन दास मुंशी सरकार के साथ व्यवधान खत्म करने का उपाय सुझाते थे।

भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का समापन शिक्षा में एआई-संचालित परिवर्तन के साझा संकल्प के साथ संपन्न

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित,भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026, आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारत के शिक्षा तंत्र के एआई-संचालित परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

दूसरे दिन दो सत्र आयोजित किए गए:

दिन 2 – सत्र 1: शासन मंच और स्केलेबल एआई सिस्टम

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में इस सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राज्य एआई-सक्षम प्लेटफार्मों का उपयोग करके निगरानी-आधारित शासन से हस्तक्षेप-आधारित शासन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डैशबोर्ड वास्तविक समय में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं तथा एकीकृत छात्र-शिक्षक-विद्यालय प्रणालियाँ खंडित उपकरणों का स्थान ले रही हैं। चर्चा ने इस बात पर बल दिया कि एआई को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए स्वतंत्र समाधानों के बजाय राज्यव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र प्लेटफार्मों की आवश्यकता होगी।

दिन 2 – सत्र 2: बहुभाषी एआई, शिक्षक सशक्तिकरण और अभ्यास-आधारित शिक्षण

आईआईएम मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में इस सत्र में बहुभाषी एआई के समान राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग के लिए इसकी अनिवार्यता पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि एआई को एक समान डिजिटल टेम्पलेट्स को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षकों की सक्रियता को मजबूत करना चाहिए और प्रासंगिक शिक्षण पद्धति का समर्थन करना चाहिए। अभ्यास-आधारित शिक्षण ढांचों से शिक्षार्थियों की सहभागिता में सुधार देखा गया और राज्यों ने शिक्षक सहायता, छात्र अधिगम और शासन के लिए एआई को एकीकृत करने वाले परिपक्व मॉडल प्रस्तुत किए।

चर्चाओं के दौरान, तीन मुख्य निष्कर्ष सामने आए:

भारत में शिक्षा में एआई के मजबूत समाधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए इन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता

है।

शिक्षण परिणामों में सुधार लाने के लिए शिक्षक सहयोग सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

अगले चरण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय मंच की आवश्यकता है।

इन सत्रों के बाद एक समीक्षा सत्र आयोजित किया गया जिसमें विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता सचिव श्री संजय कुमार और उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी ने भाग लिया। आईआईटी मद्रास के निदेशक, प्रोफेसर वी. कामाकोटी, एआई के क्षेत्र में काम कर रहे प्रमुख स्टार्टअप के अकादमिक नेता, शोधकर्ता और संस्थापक, शिक्षा विभाग ने भाग लिया। पिछले सत्रों के चारों वक्ताओं ने अपने-अपने तकनीकी सत्रों से प्राप्त मुख्य बिंदुओं और परिणामों को प्रस्तुत किया।

श्री संजय कुमार ने कहा कि पिछले ढाई दिनों की चर्चा अत्यंत उत्साहवर्धक रही। इसमें शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए राज्यों, संस्थानों और संगठनों द्वारा देश भर में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को दर्शाया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित शिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से वैयक्तिकरण के साथ-साथ व्यापकता को संयोजित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि समान पहुंच को केंद्र में रखते हुए ये नवाचार सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं, समावेशन को मजबूत कर सकते हैं और शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने अनुसंधान, विकास और मजबूत संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर निवेश के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तारित करने के लिए सहयोगी मंचों के निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक संप्रभु वृहद भाषा मॉडल जैसी रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाते हुए मातृभाषा में आनंददायक और सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देने से भारत की भाषाई विविधता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी।

प्रोफेसर वी. कामाकोटी ने कहा कि भारत के पास मजबूत एआई समाधान हैं, लेकिन व्यापकता, समन्वय और अंतरसंचालनीयता में मुख्य जनादेश अभी भी बना हुआ है। । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए, भाषाई विविधता को संरक्षित करना चाहिए और विभाजन पैदा किए बिना सभी शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना चाहिए।

भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 ने भारत के शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभूतपूर्व प्रतिनिधियों को एक साथ लाया, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। 3,100 पंजीकरण, 2,000 छात्र , 600 से अधिक प्रतिनिधि और लगभग 120 प्रदर्शक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से प्रेरित नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे थे। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में नीति निमार्ता, राज्य सरकारें, शोधकर्ता, परोपकारी संस्थाएं और शिक्षा-तकनीक के नवप्रवर्तक एकत्रित हुए ताकि यह विचार किया जा सके कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूली शिक्षा को कैसे बदल सकती है—विशेष रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन), शिक्षक प्रभावशीलता, शासन दक्षता और बहुभाषी समावेशन के क्षेत्र में।

भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 ने नीति निमार्ताओं, शिक्षकों, प्रौद्योगिकी नेताओं और शैक्षणिक विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए एक सहयोगात्मक मंच प्रदान किया ताकि शिक्षा में एआई-संचालित परिवर्तन पर विचार-विमर्श किया जा सके।

क्यूए-औद्योगिक सम्मेलन में डिजिटल बदलाव को रक्षा गुणवत्ता आश्वासन की भरोसेमंद और समयबद्ध नींव के तौर पर दिखाया गया

(जीएनएस)।

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए)-औद्योगिक सम्मेलन, जिसका विषय था 'ट्रेसेबिलिटी, स्पीड एंड ट्रस्ट - लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्टर क्वालिटी एश्योरेंस', 13 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, क्यूए संगठन, रक्षा शिपयार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और प्रमुख निजी उद्योग साझेदारों का वरिष्ठ नेतृत्व एक ही मंच पर टेक्नोलॉजी-ड्रिवन क्वालिटी एश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक साथ आया।

सम्मेलन ने रक्षा निर्माण मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया को फिर से परिभाषित करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव भूमिका पर जोर दिया। चर्चा उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक किसी उत्पाद की यात्रा के हर चरण पर नजर रखने, प्रक्रियात्मक समय सीमा को कम करने, निरीक्षण और प्रमाणन में पारदर्शिता बढ़ाने और गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों और उद्योग के बीच विश्वास को बढ़ावा देने वाला एक रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क बनाने पर फोकस थी। चर्चाओं में यह साफ आम सहमति दिखी कि कॉम्प्लेक्स शिपबिल्डिंग और डिफेंस प्रोडक्शन प्रोग्राम में स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पाने के लिए डिजिटल टूल्स, डेटा-सेंट्रिक मेथडोलॉजी और कोलेबोरेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क को जोड़ना जरूरी है।

इस कार्यक्रम का एक बड़ा नतीजा इंडियन नेवल एंड मरीन इंडस्ट्री - ए कैपेबिलिटी कैटलॉग का रिलीज होना था। यह एक बड़ा कलेक्शन है जिसका मकसद देसी इंडस्ट्रियल क्षमताओं को सुव्यवस्थित दृश्यता देना और सर्विसेज और घरेलू निर्माण इकोसिस्टम के बीच मजबूत जुड़ाव को आसान बनाना है। कॉम्बैट सिस्टम और सेंसर के इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन मॉडल पर जॉइंट सर्विस गाइडलाइंस का ऐलान, स्टेकहोल्डर्स के बीच टेक्निकल और क्वालिटी डेटा के स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और बिना रुकावट डिजिटल एक्सचेंज की दिशा में एक अहम पड़ाव था। पात्र औद्योगिक साझेदारों को उनके प्रमाणित गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए ग्रीन चैनल स्टेटस देना और सेल्फ-सर्टिफिकेशन देना, एक भरोसे पर आधारित, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की ओर एक प्रोग्रेसिव बदलाव को दिखाता है जो निरंतरता, विश्वसनीयता और प्रक्रिया परिपक्वता का प्रतिफल देता है।

तकनीकी सत्र में जहाज निर्माण के लिए डिजिटल क्यूए, तेजी से बदलते औद्योगिक माहौल में पॉलिसी कम्प्लायंस, और नौसेना जहाज निर्माण में गुणवत्ता आश्वासन चुनौतियों और स्पेयर्स के लिए रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर पर गहरी और आगे की सोच वाली चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने व्यावहारिक अनुभव, सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नई जरूरतें शेयर कीं, जिससे आइडियाज का अच्छा लेन-देन हुआ और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक्शनेबल रास्तों की पहचान हुई। बातचीत में रियल-टाइम डेटा विज़िबिलिटी, इंटीग्रेटेड इंस्पेक्शन प्लानिंग, एक जैसा डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क-बेस्ड सर्टिफिकेशन मॉडल और डिजाइन स्टेज से लेकर क्वालिटी प्लानिंग में इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

इंडियन नेवी के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल बी शिवकुमार और अन्य वरिष्ठ लोगों ने अपने भाषण में भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बदलते प्रकृति और टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम और नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्ता आश्वासन अब कोई आखिरी कार्य नहीं है, बल्कि डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग और लाइफसाइकल सपोर्ट में शामिल एक लगातार चलने वाली, टेक्नोलॉजी सक्षम प्रक्रिया है। क्यूए प्रक्रिया को आत्मनिर्भर भारत के नेशनल विजन के साथ जोड़ने और काबिल इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए भरोसे पर आधारित कम्प्लायंस माहौल बनाने के महत्व पर भी खास तौर पर जोर दिया गया।

स्टार्टअप इंडिया ने 2.07 लाख उपक्रमों को मान्यता दी, 21.9 लाख नौकरियां पैदा कीं; सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए फंडिंग बढ़ाई

सरकार ने बीआरएपी, जन विश्वास, 80-आईएसी लाभ और ईएसओपी टीडीएस राहत के जरिए स्टार्टअप्स के लिए कर राहत को आसान बनाया, और बढ़ाया

(जीएनएस)।

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की पहल है। 31 दिसंबर 2025 तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कुल 2,07,135 एंटिटीज को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है, और ऐसे स्टार्टअप्स ने 21.9 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां सर्जित की हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और ऐसे स्टार्टअप्स द्वारा सर्जित की गई नौकरियों की वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-क में दी गई हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार तीन फ्लैगशिप स्कीम लागू कर रही है, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस)। ये स्कीम अलग-अलग क्षेत्र के स्टार्टअप्स को उनके बिजनेस चक्र के अलग-अलग चरण पर फंडिंग के अवसर देती हैं।

एफएफएस को उपक्रम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) चलाता है। यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड्स (एआईएफ) को पूंजी देता है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत समर्थित एआईएफ ने 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,371 चुने हुए स्टार्टअप्स में 25,547.98 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। एफएफएस के तहत समर्थित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश की गई राशि का वर्ष-दर-वर्ष विवरण अनुलग्नक-कक में दिया गया है। ऐसे समर्थित स्टार्टअप्स ने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां सर्जित की हैं।

एसआईएसएफएस इनक्यूबेटर के जरिए सीड स्टेज स्टार्टअप को ग्रांट, कन्वर्टिबल डिबेंचर या डेट या डेट-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में वित्तीय मदद देता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है। 31 दिसंबर 2025 तक, स्कीम के तहत चुने गए इनक्यूबेटर ने 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,271 स्टार्टअप को 590.93 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दी है। ऐसे सपोर्टेड स्टार्टअप ने 22,600 से ज्यादा नौकरियां सर्जित की हैं।

सीजीएसएस को पात्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए स्टार्टअप्स को क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बदले निर्धारित सीमा तक गारंटी देकर डेट फंडिंग देने के लिए लागू किया गया है। सीजीएसएस को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड चलाती है और यह 1 अप्रैल 2023 से चालू हो गया है। 31 दिसंबर 2025 तक, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप बॉरोअर्स को लगभग 808.18 करोड़ रुपये के 334 ऋण की गारंटी दी गई है। ऐसे सपोर्टेड स्टार्टअप्स ने 23,700 से ज्यादा नौकरियां सर्जित की हैं।

एफएफएस और एसआईएसएफएस योजनाओं के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन किए गए है। योजनाओं के प्रभाव आकलन के अनुसार, सपोर्टेड स्टार्टअप्स ने राजस्व और रोजगार सर्जन जैसे आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की रिपोर्ट दी है। इसके अलावा, निवेशकों के क्षमता निर्माण को इनेबल किया गया है, और अलग-अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया है।

विनियामक अनुपालन को आसान बनाने और स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के लिए किए गए सरकार के उपाय:

पूरे देश में विनियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत कई पहल की हैं, जिसमें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी असेसमेंट, जन विश्वास और बिजनेस और नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम करना, और सेवाओं के लिए प्रशासनिक लागत के मामले में दिक्कत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनमें सुधार करने के लिए कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन (सीओआर) अभ्यास शामिल है। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश खुद की पहचान करने के अभ्यास में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिससे अलग-अलग अनुपालन को सफलतापूर्वक कम किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस के लिए कर से जुड़े अलग-अलग लाभ पाने के लिए कई पहल, नीतिगत उपाय और सुधार किए हैं। इनमें आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80-क्अउ के तहत लाभ से जुड़ी कटौती, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) से जुड़ी आय के मामले में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को टालना, नुकसान को आगे बढ़ाने और सेट-ऑफ करने में छूट, और एलिजिबल इनक्यूबेटर में मौजूद उद्यमों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट इत्यादि शामिल हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, जीएसटी के तहत सरकार ने आम नीतिगत उपाय किए हैं। विवरण अनुलग्नक-कक्क में दिया गया है।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्टार्टअप्स को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कुछ अनुपालन में छूट/रियायत दी गई है। विवरण अनुलग्नक -कक्ष में दिया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

2025 में 7 लाख से अधिक नोटिस, 5.6 लाख प्रतिबंध: स्पैम टेलीमार्केटर्स पर टीआरएआई की सख्ती बढ़ी

डीएनडी ऐप के माध्यम से उपयोगकताओं द्वारा 17 लाख से अधिक स्पैम शिकायतें दर्ज की गई

टीआरएआई के यूसीसी प्रवर्तन ढांचे के तहत लगभग 90,000 बार-बार उल्लंघन करने वालों पर छह महीने तक का विस्तारित संचार प्रतिबंध लगाया गया

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने वर्ष 2025 के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के प्रवर्तन और डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) प्रणाली के तहत उपभोक्ता जुड़ाव पर अपना वार्षिक अपडेट जारी किया है, जिसमें स्पैम टेलीमार्केटिंग के खिलाफ नियामक कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 2025 के दौरान, यूसीसी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) को 7,31,120 नोटिस जारी किए गए। प्रगतिशील प्रवर्तन उपायों के तहत, 4,73,075 संस्थाओं पर एक महीने के लिए संचार प्रतिबंध लगाए गए, जबकि 89,936 बार-बार उल्लंघन करने वालों पर छह महीने के लिए संचार प्रतिबंध लगाए गए। इसके अतिरिक्त, लगातार नियमों का पालन न करने के कारण वर्ष के दौरान 1,84,482 दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काट दिया गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2024 से अब तक 21.05 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटा जा चुका है, जो लगातार स्पैम नेटवर्क पर अंकुश लगाने और दूरसंचार प्रणाली में अनुपालन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे गहन प्रयासों को दर्शाता है।

स्पैम की रिपोर्टिंग के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयासों से प्रवर्तन कार्रवाई को समर्थन मिल रहा है। 2025 में, सभी चैनलों के माध्यम से कुल 31.09 लाख यूसीसी शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 17.06 लाख शिकायतें - आधे से अधिक - डीएनडी एप्लिकेशन के माध्यम से जमा की गईं, जो अवांछित संचार की रिपोर्टिंग में उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करती हैं।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, टीआरएआई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने कहा:

ह्लटीआरएआई के 2025 के प्रवर्तन प्रयास इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण में स्पष्ट सुधार का अनुभव होना चाहिए। डीएनडी प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने उल्लंघनों की तेजी से पहचान करने और लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिक निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया है।ह्व

मासिक आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे वर्ष पंजीकृत टेलीमार्केटरों के खिलाफ शिकायतों की तुलना में अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के खिलाफ शिकायतों की संख्या कहीं अधिक रही। यह प्रवृत्ति नियामक ढांचे से बाहर काम करने वाली अनधिकृत और गैर-अनुपालनकारी संस्थाओं को लक्षित करने पर टीआरएआई के फोकस को और मजबूत करती है।

टीआरएआई ने दोहरी रणनीति अपनाई है, जिसके तहत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वैध, सहमति-आधारित वाणिज्यिक संचार को सक्षम बनाया जा रहा है, साथ ही साथ अपंजीकृत संस्थाओं से अवांछित संचार को रोकने के लिए डीएलटी (ब्लॉकचेन) आधारित पंजीकरण, एआई-आधारित स्पैम पहचान, निर्दिष्ट संख्या श्रृंखला का अनिवार्य उपयोग, मजबूत शिकायत तंत्र और गैर-अनुपालन करने वाले प्रेषकों का डिस्कनेक्शन जैसे नियामक, तकनीकी और प्रवर्तन उपायों को भी लागू किया जा रहा है।

डीएनडी इकोसिस्टम के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डीएनडी ऐप इंस्टॉलेशन में 2025 में साल-दर-साल 84.43% की वृद्धि हुई, जिससे कुल इंस्टॉलेशन की संख्या 28.08 लाख हो गई, जबकि 2024 में यह 15.22 लाख थी।

उपभोक्ताओं द्वारा अधिक रिपोर्टिंग और प्रवर्तन तंत्रों को मजबूत करने के संयोजन से उल्लंघनकताओं की तेजी से पहचान और अधिक निर्णायक नियामक कार्रवाई संभव हो पाई है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव के मद्देनजर सीहोर रेलवे स्टेशन पर व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था

रतलाम 13 फरवरी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान संभावित अतिरिक्त यात्री भीड़ को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से समायोजित करने के लिए सीहोर रेलवे स्टेशन पर व्यापक स्तर पर विशेष तैयारियां की गई हैं।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 14 से 20 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए रतलाम रेल मंडल प्रशासन द्वारा सीहोर स्टेशन बहुआयामी कार्ययोजना लागू की गई है। इसके दिए सुरक्षा, संरक्षा, यात्री सुविधा, ट्रेन परिचालन आदि जैसे सभी आधारभुत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव एवं विशेष रेल सेवाएं

महोत्सव अवधि के दौरान 13 से 22 फरवरी 2026 तक सीहोर स्टेशन पर 21 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उज्जैन से सीहोर/भोपाल के मध्य 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्री भार को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की भी योजना तैयार रखी गई है।

प्लेटफार्म एवं आवागमन व्यवस्था में विशेष परिवर्तन

भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत मेला अवधि के दौरान सीहोर स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल (ऋ्ढइ) से आवागमन अस्थायी रूप से बंद रखा गया है।

भोपाल की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें प्लेटफार्म संख्या 2 से संचालित होंगी।

उज्जैन की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें प्लेटफार्म संख्या 1 से संचालित होंगी।

भोपाल की ओर जाने वाले यात्रियों को भोपाल एंड स्थित अंडरपास से सीधे प्लेटफार्म 2 पर प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि उज्जैन की ओर जाने वाले यात्री प्लेटफार्म 1 की ओर से सीधे प्लेटफार्म 1 पर पहुंचेंगे। किस प्लेटफार्म से कौन-सी ट्रेन जाएगी, इसकी नियमित उद्घोषणा की जा रही है।

क्राउड होल्डिंग एरिया एवं बैरीकेडिंग

स्टेशन परिसर में विशेष ' क्राउड होल्डिंग एरिया ' बनाया गया है, जहां यात्रियों को ट्रेन आगमन से पूर्व रोका जाएगा तथा ट्रेन आने पर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश दिया जाएगा, जिससे प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो। प्लेटफार्म एवं स्टेशन परिसर में व्यापक बैरीकेडिंग की गई है तथा प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था

भीड़ प्रबंधन हेतु फ्ढ्ऋएवं ऋ्फ्ढ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं। स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग मंडल कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जा सकेगी।

मेला अवधि में रतलाम मंडल की सिविल डिफेंस टीम को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, जिन्हें किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए चिकित्सा सुविधा की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

यात्री सुविधाओं का विशेष प्रबंध

यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशन पर पीने के पानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, नियमित साफ-सफाई, डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्लेटफार्म संख्या 1 एवं 2 की ओर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं। टिकट जांच एवं अतिरिक्त टिकट निर्गमन के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है।

रेलवे द्वारा स्टेशन क्षेत्र के साथ-साथ मेला क्षेत्र में भी दिशा-सूचक बैनर लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो।

मंडल रेल प्रबंधक द्वारा निरीक्षण

रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री अश्वनी कुमार ने 13 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीहोर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर, की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ह्वभीड़ प्रबंधन के लिए मंडल द्वारा व्यापक और सुविचारित तैयारी की गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ह्व

समन्वित प्रयास

रतलाम मंडल द्वारा वाणिज्य, परिचालन, सुरक्षा, विद्युत, यांत्रिक, इंजीनियरिंग सहित सभी विभागों के समन्वित प्रयास से मेला अवधि पूर्व ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थीं। स्थानीय प्रशासन के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाओं से उन्हें अवगत कराया गया है।

पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान यात्रियों के सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित आवागमन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

जनसंपर्क विभाग
पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के नागरिकों के लिए 28 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्थान कराई गईं नई 28 ई-बसें साइबर सिक्योरिटी तथा फायर सेफ्टी सिस्टम से सज्ज

बहुत ही कम समय में पूर्ण हुए ई-बस प्रोजेक्ट से एएमटीएस के बेड़े में ग्रीन मोबिलिटी का नया अध्याय शुरू

गांधीनगर, 13 फरवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) की जीवनडोर समान अहमदाबाद महानगर पालिका परिवहन सेवा (एएमटीएस) के बेड़े में 28 नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का शुक्रवार को लोकार्पण किया।

एएमटीएस में समय-समय पर कुल 225 नई ई-बसों को जोड़ा जाना है और इसके साथ ही नगरजनों को अधिक सुविधाजनक एवं ग्रीन परिवहन प्राप्त होगा। इन 225 ई-बसों के संचालन से प्रतिवर्ष लगभग 75000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी।

यह प्रोजेक्ट देश के सबसे तेज क्रियान्वयन वाले प्रोजेक्ट्स में एक है, जिसमें पूरी निविदा प्रक्रिया केवल 6 महीनों में पूरी कर केवल 3 महीनों में बसों की डिलीवरी सुनिश्चित की गई है।

यात्रियों की सुरक्षा के मामले में ये बसें देश में अद्वितीय हैं। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों में अनिवार्य साइबर सिक्योरिटी तथा सेफ्टी ऑडिट को लागू किया गया है। इसके अलावा, हर बस में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (एफडीएसएस) कार्यरत कर यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

इस अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, उप महापौर श्री जतिन पटेल, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी, शासक पक्ष के नेता श्री गौरांगभाई प्रजापति, सचेतक श्रीमती शीतल डागा, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, स्थानीय विधायक, एएमटीएस अध्यक्ष श्री धरमशीभाई देसाई, मनपा एवं एएमटीएस के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

लखनऊ में शिया समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, ढट शहबाज शरीफ का जलाया फोटो, मामला जानिए

पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का फोटो जलाया और नारेबाजी की।

(जीएनएस)।

लखनऊः पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का फोटो जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। भीड़ ने पाकिस्तान मुदार्बाद और शिया अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पाकिस्तान में शिया समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है वहां की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। प्रदर्शन में प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना

कल्वे जवाद भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

मौलाना कल्वे जवाद ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद दहशतगर्द ताकतों को संरक्षण देती है और वहां अल्पसंख्यकों, खासकर शिया मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्द है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उसे आतंकी मुल्क घोषित करने पर विचार करना चाहिए। मौलाना कल्वे जवाद ने यह भी कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में मजहब के नाम पर हिंसा हो रही है, जो मानवता के लिए खतरा है। उन्होंने इजरायल सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए उसे आतंकी हुकूमत करार दिया और कहा कि निर्दोष लोगों पर हो रहे हमलों की वैश्विक स्तर पर निंदा होनी चाहिए।

प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, हालांकि माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आया। मौके पर स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शिया समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मांग की कि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए और वहां हो रहे अत्याचारों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगे और बड़े आंदोलन किए जाएंगे।

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 11 पदाधिकारियों ने छोड़ी बीजेपी, बोले- उद्देश्य से भटक गई पार्टी

लखनऊः (जीएनएस)। लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ी है. साथ ही यह भी कहा है कि पार्टी उद्देश्य से भटक गई है.

यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ी है. लखनऊ में एक साथ बीजेपी 11 पदाधिकारियों के पार्टी छोड़ने से सियासी गलियारों में चचाओं का बाजार गर्म हो गया.

जानकारी के मुताबिक, यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है. पार्टी से इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि वह अब पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे. पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण

किया गया था, पार्टी उस उद्देश्य से भटक गई है.

सवर्ण बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीजेपी छोड़ने वाले पदाधिकारी बख्शी तालाब के कुम्हारवां मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने कहा है कि यह कानून लागू करके हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने समस्त पदों से इस्तीफा देते हैं.

बीजेपी से इन पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

जानकारी के मुताबिक, यूजीसी के विरोध में मंडल उपाध्यक्ष आलोक सिंह, मंडल मंत्री महावीर सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक मोहित मिश्रा, शक्ति केंद्र संयोक वेद प्रकाश सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक नीरज पांडेय, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री राज विक्रम सिंह, पूर्व मंडल मंत्री अभिषेक अवस्थी, बूथ अध्यक्ष विवेक सिंह और पूर्व सेक्टर संयोजक कमल सिंह का नाम इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों में शामिल है.

इस्तीफे में क्या कहा?

पार्टी से इस्तीफा अंकित तिवारी ने कहा कि, "मैं अपने समस्त पदों से इस्तीफा देता हूं क्योंकि जो हमारे प्रेरणा स्त्रोत पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था, पार्टी उस उद्देश्य से भटक रही है. पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारियों द्वारा यूजीसी कानून लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इसी को देखते हुए मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं"

व्यापार और निवेश विधि केंद्र ने विश्व व्यापार संगठन अध्यक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की

(जीएनएस)।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार और निवेश विधि केंद्र ने बेनेट विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन अध्यक्षता कार्यक्रम के तहत 6 से 8 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में तीसरी सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ-बेनेट अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट (वास्तविक अदालती कार्यवाही का अनुकरण करने वाली काल्पनिक अदालत) प्रतियोगिता 2026 आयोजित की।

तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता ने विधि संकाय के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिनियम और श्रम मानकों से संबंधित समकालीन मुद्दों के बारे में जानकारी के लिए अकादमिक मंच प्रदान किया। प्रतियोगिता में भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विभिन्न दौर का मूल्यांकन विधि क्षेत्र, शिक्षा जगत और नीति संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों ने किया।

इसमें औद्योगिक दुर्घटना और उसके बाद के नियामक घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप मुक्त व्यापार समझौते के तहत श्रम मानकों और व्यावसायिक सुरक्षा दायित्वों के कथित उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संवैधानिक मूल्यों, न्यायिक तर्कशक्ति और विधि सम्मत शासन बनाए रखने में विधि संस्थानों की भूमिका पर बल दिया। बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज सिंह ने नीति-उन्मुख विधि शिक्षा को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालयों की भूमिका का उल्लेख किया। अन्य वक्ताओं ने क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन की समझ बढ़ाने में विश्व व्यापार संगठन के विधि संबंधी मुकदमों के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए न्याय व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में विधि शिक्षा की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक निष्ठा और व्यावसायिक उत्तरदायित्व को रेखांकित किया। समापन सत्र में प्रतियोगिता परिणामों की घोषणा और अनुसंधान, पैरवी और समग्र प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस प्रतियोगिता ने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कानून और वैश्विक आर्थिक शासन में उन्नत अध्ययन और व्यावहारिक भागीदारी को बढ़ावा देने में शैक्षणिक और नीतिगत संस्थानों की भूमिका दर्शाई।

पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई, पीएमएफएमई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सतत और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहलें

एकीकृत और अंतर-क्षेत्रीय शीत श्रृंखला नेटवर्क में चुनौतियाँ

(जीएनएस)।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आपूर्ति श्रृंखला और संस्थागत बुनियादी ढांचे में कमियों, कृषि उपज की बबार्दी, प्रसंस्करण के निम्न स्तर, कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच कमजोर संबंधों और ऋण तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण (पीएमएफएमई) जैसी योजनाओं को देश भर में लागू करके इस क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई के तहत प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके सौर, बायोमास और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का समर्थन करता है। जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-संचालित

विकास को बढ़ावा मिलता है। मंत्रालय पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को अनुदान सहायता और सब्सिडी जारी करने पर विचार करने के लिए एक शर्त के रूप में पर्यावरण और स्थिरता मानदंडों के सख्त अनुपालन को भी प्रोत्साहित करता है। इस संबंध में, यह मंत्रालय पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देशों के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से आग्रह करता है कि वह (i) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना की वैध स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) प्रस्तुत करे और (ii) ऊर्जा-कुशल शीत प्रणालियों को अपनाना जो गैर-ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (नॉन-ओडीएस) और कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (जीडब्ल्यूपी) वाले रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं ताकि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके, क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना (शीत श्रृंखला सहित) का विकास राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन उद्देश्यों के अनुरूप हो।

यूपीएफ को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए गए

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विज्ञान आधारित खाद्य मानक निर्धारित करेगा

खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में नियमित निगरानी, निरीक्षण और बिना क्रम नमूने लिए जाते हैं

(जीएनएस)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

खाद्य सुरक्षा एवं सेवा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए 'आज से थोड़ा कम' नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आहार में बदलाव के माध्यम से धीरे-धीरे वसा, नमक और चीनी का सेवन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

खाद्य सुरक्षा जागरूकता और स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई ने देश भर में 'ईट राइट इंडिया' अभियान के तहत सोशल मीडिया पर "हर लेबल कुछ कहता है" नामक जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को

खाद्य लेबल की बेहतर समझ प्रदान करके उन्हें सोच-समझकर आहार संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। खाद्य लेबल में उत्पाद के पोषण मूल्य, सामग्री और संभावित एलर्जी कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें पूर्व-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग से संबंधित व्यापक प्रावधान दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विद्यालयों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन एवं संतुलित आहार) विनियम, 2020 को भी अधिसूचित किया गया है, जिसमें विद्यालय परिसर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विद्यालय परिसर के भीतर और आसपास संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देशभर के उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारी वर्ष भर विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और बिना क्रम नमूने लेते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच की जा सके।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह बात कही।

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने आवास वित्त के बदलते परिदृश्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध आवासों के व्यापक आंकड़ों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय आवास विनिमय जैसी व्यवस्था जैसे अभिनव समाधानों पर विचार करने का प्रस्ताव रखा

(जीएनएस)।

नेशनल हाउसिंग बैंक और एशिया पैसिफिक यूनियन फॉर हाउसिंग फाइनेंस (एपीयूएचएफ) द्वारा 12 और 13 फरवरी 2026 को भारत मंडपम में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

आज भारत मंडपम में आयोजित आवास वित्त के बदलते परिदृश्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सम्मेलन का मुख्य विषय समावेशिता, स्थिरता और सतत विकास था।

अपने संबोधन में माननीय मंत्री जी ने आवास वित्त को प्रत्येक नागरिक के लिए अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने परिवहन से जुड़े आवास विकास और दूरदर्शी नीतिगत नवाचारों सहित एकीकृत शहरी नियोजन की

आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध आवासों के व्यापक आंकड़ों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय आवास विनिमय जैसी व्यवस्था जैसे अभिनव समाधानों का पता लगाने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि नागरिकों को उनके कार्यस्थलों के करीब उपयुक्त घरों की पहचान करने में मदद मिल सके और आवागमन के समय को कम करने के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी संपत्ति विनिमय को सुविधाजनक बनाया जा सके।

उन्होंने नीति आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 2021 में भारत की शहरी आबादी 50 करोड़ थी और 2050 तक इसके 85 करोड़ से अधिक हो जाने का अनुमान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन से पूरे देश में किफायती आवास की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इस विकास के लिए तैयारी की तात्कालिकता पर जोर देते हुए, श्री मनोहर लाल ने आवास के लिए पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) मॉडल के माध्यम से मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास का आह्वान किया, जिससे आवास अधिक सुलभ और टिकाऊ बन सके।

इसके अलावा, उन्होंने बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और राष्ट्रीय आवास बैंक सहित वित्तीय संस्थानों से देश भर में आवास भंडार का विस्तार करने के लिए सहयोग करने और अधिक ऋण सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

अपने संबोधन के समापन में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया - यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पात्र नागरिक को एक सम्मानजनक घर तक पहुंच प्राप्त हो, जो सभी के लिए आवास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस कार्यक्रम में भारत सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, विश्व भर के देशों के संस्थानों, निजी इक्विटी कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के प्रतिष्ठित पेशेवरों और संसाधनों ने भाग लिया है।

यह सम्मेलन संवाद, ज्ञान के आदान-प्रदान और रणनीतिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो किफायती आवास और शहरी विकास में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

यूपी के लखनऊ, वाराणसी और मिजार्पुर की कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, एक्शन में पुलिस

राजधानी लखनऊ, वाराणसी और मिजार्पुर कचहरी में बम धमकी के बाद पुलिस ने परिसर खाली कराकर सघन जांच शुरू की. अभी तक कोई विस्फोटक नहीं मिला. साइबर सेल ईमेल की जांच कर रही है. सुरक्षा बढ़ाई गई, जांच जारी है. आज सुबह से ही जिला जज को ईमेल से यह धमकी दी गई.

(जीएनएस)।

वाराणसी/लखनऊ/मिजार्पुर. राजधानी लखनऊ, मिजार्पुर और वाराणसी कचहरी परिसर में शुक्रवार सुबह बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. वाराणसी में जिला जज संजीव शुक्ला को गुरुवार रात उनके आधिकारिक ई-मेल पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कचहरी को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद शुक्रवार दोपहर लखनऊ जिला जज की कोर्ट में ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली. अभी जांच चल ही रही थी कि खबर आई मिजार्पुर कचहरी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल हिअ. इस सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई

और तीनों जगह पूरे परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया.

धमकी मिलने के बाद अपर पुलिस कमिश्नर, वरुणा जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार, कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा समेत भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) की तीन टीमें और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे. सुबह से शुरू हुई चेकिंग में दो घंटे तक विभिन्न हिस्सों की जांच की गई, लेकिन अभी तक किसी बम या विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है. अभियान जारी है और हर कोने की बारीकी से जांच हो रही है.

जिला जज और डीसीपी ने खुद परिसर का भ्रमण किया तथा स्थिति का जायजा लिया. अधिवक्ताओं ने भी अपने चैंबरों और संदिग्ध सामानों की जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी है ताकि कोई जोखिम न रहे. साइबर सेल ने ई-मेल की जांच शुरू कर दी है, जिसमें धमकी भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाया जा रहा है. कुछ सूत्रों के अनुसार, ई-मेल तमिलनाडु से भेजा गया है और इसमें वाराणसी के अलावा अन्य स्थानों पर भी धमकी का जिक्र है.

2007 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट

यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि वाराणसी में 3 नवंबर 2007 को हुए सीरियल ब्लास्ट में तीन अधिवक्ताओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे. उस पुरानी घटना की याद से लोगों में डर का माहौल है. पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने तक परिसर में सतर्कता बरती जा रही है और न्यायिक कार्य प्रभावित न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन साइबर टीम तेजी से काम कर रही है. अगर धमकी झूठी साबित हुई तो भी भेजने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यह घटना न्यायिक परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और ऐसे मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया की जरूरत को रेखांकित कर रही है. जांच के नतीजे आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर ताला, जमा पूंजी के लिए धरने पर बैठे खाताधारक; लेनदेन में अनियमितताओं का मामला

लखनऊ , (जीएनएस)।

लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर खाताधारकों ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। ग्राहकों ने जमा रकम लौटाने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले, जबकि बैंक प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

लखनऊ के पारा स्थित शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर में बृहस्पतिवार सुबह ग्यारह बजे उस समय भावुक और तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर खाताधारकों ने बैंक बंद कर धरना शुरू कर दिया।

मेहनत की कमाई को लेकर चिंतित ग्राहक

अपनी मेहनत की कमाई को लेकर चिंतित ग्राहक शाखा के सामने बैठ गए। रकम वापस दिलाने की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शन कर रहे

खाताधारकों की आंखों में आक्रोश के साथ-साथ बेबसी भी साफ झलक रही थी। उनका आरोप है कि खातों से जुड़े लेनदेन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और इस पूरे प्रकरण में बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

जीवन भर की बचत दांव पर लगी

खाताधारकों का कहना है कि उनकी जीवन भर की बचत दांव पर लगी है, ऐसे में जब तक रकम वापस नहीं मिलती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सूचना पर पहुंची पारा पुलिस ने मौके पर स्थिति संभालने का प्रयास किया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की।

लेकिन, खाताधारक अपनी मांगों पर डटे रहे। एहतियात के तौर पर परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बैंक प्रबंधन की ओर से दोपहर तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। फिलहाल, परिसर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और खाताधारकों का धरना जारी है।

भारत ने बर्लिन में यूरोपीय फिल्म बाजार 2026 में 'भारत मंडप' के शुभारंभ के साथ सिनेमा, संस्कृति और नवाचार का प्रदर्शन किया

भारतीय फिल्मकारों की सक्रिय भागीदारी भारतीय सिनेमा में बढ़ती वैश्विक रुचि को दिखाती है

क्रिएट इन इंडिया के विजेताओं और राज्यों ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया

भारत ने ईएफएम इनोवेशन हब 2026 में अत्याधुनिक क्रिएटिव-टेक इनोवेशन और एवीजीसी-एक्सआर क्षमताओं को प्रदर्शित किया

(जीएनएस)।

बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित यूरोपीय फिल्म बाजार (ईएफएम) 2026 में अपनी मजबूत और बहुआयामी उपस्थिति के साथ भारत ने औपचारिक रूप से बाजार में अपने आधिकारिक मंच 'भारत मंडप' का उद्घाटन किया, जो सिनेमा, संस्कृति और रचनात्मक प्रौद्योगिकियों में देश की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करता है। मंडप का उद्घाटन जर्मनी में भारत के राजदूत श्री अजीत विनायक गुप्ते ने जाने-माने इंटरनेशनल मार्केट लीडर्स, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों और भारतीय फिल्म एवं नवाचार प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में किया।

उद्घाटन समारोह में रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत-जर्मनी के बीच बढ़ती सहभागिता को प्रदर्शित किया गया। विशिष्ट प्रतिभागियों में बर्लिनले प्रो की निदेशक और यूरोपीय फिल्म बाजार की हेड सुश्री तांजा मीस्नर, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली फिल्म बाजारों में से एक का नेतृत्व करती हैं; ईएफएम के सेल्स और डिजाइन हेड श्री पीटर डोम्श, जो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और रणनीतिक उद्योग जुड़ाव को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं; और टैगोर सेंटर की निदेशक सुश्री तृषा सखलेचा, जिनका काम भारत और जर्मनी के बीच कलात्मक व सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने में अहम रहा है, शामिल थीं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के वरिष्ठ अधिकारियों, बर्लिन में भारतीय दूतावास के सदस्यों और देश के विकसित होते क्रिएटिव इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया।

भारतीय फिल्मकारों ने वैश्विक साझेदारी का विस्तार किया

इस वर्ष यूरोपीय फिल्म बाजार में भारत की उपस्थिति कहानी कहने की उत्कृष्टता और नवाचार आधारित भागीदारी के मजबूत मेल के साथ खास है। एक प्रमुख आकर्षण नौ भारतीय फिल्मकारों की भागीदारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय निमार्ताओं, बिक्री एजेंटों, वितरकों और फेस्टिवल प्रोग्रामर्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। उनकी उपस्थिति ग्लोबल को-प्रोडक्शन नेटवर्क्स में भारत के बढ़ते एकीकरण और विविध भाषाओं व शैलियों में भारतीय कहानियों के लिए बढ़ती अतंर्राष्ट्रीय रुचि को दिखाती है। सुव्यवस्थित बाजार बैठकों और प्रोजेक्ट डिस्कशन के माध्यम से, ये फिल्मकार ऐसी साझेदारियां तलाश रहे हैं जो पारंपरिक फिल्म व्यापार से आगे बढ़कर, सीमा पार सहयोग और दीर्घकालिक क्रिएटिव अलायंस का रूप ले सके।

भारत के तेजी से बढ़ते मीडिया-टेक और क्रिएटिव-टेक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार उभरते स्टार्ट-अप्स के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कंपनियां ऐसे समाधान प्रस्तुत करती हैं जो स्टोरीटेलिंग, टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोडक्शन को जोड़ती हैं, और यह दशार्ती हैं कि कैसे भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी नवाचार के साथ तेजी से आकार ले रही है। ईएफएम में उनकी उपस्थिति भारत के सिर्फ एक प्रमुख कंटेंट तैयार करने वाले देश से ग्लोबल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में तकनीकी प्रगति के हब के तौर पर पहचाने जाने के बदलाव का संकेत है।

भारत का प्रतिनिधित्व करते युवा नवोन्मेषक

इस प्रतिनिधिमंडल में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी) के दो विजेता भी शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण आइडिया और युवा क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स पर बात करेंगे, जिनके काम में नवाचार आधारित स्टोरीटेलिंग की भावना दिखती है।

उनकी भागीदारी इस बात को दिखाती है कि देश नए टैलेंट को आगे बढ़ाने और उभरती आवाजों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दे रहा है। महाराष्ट्र का एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित है, जो बेहतर नीति , फंडिंग ऑप्शन और फिल्म प्रोडक्शन के लिए विभिन्न संसाधनों के माध्यम से फिल्मकारों को सपोर्ट करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दिखाता है, साथ ही वैश्विक फिल्म मैप पर एक प्रमुख भागीदार के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति को मजबूत करता है। दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बढ़ावा देने, विशेष फिल्मांकन प्रोत्साहनों और मंजूरी प्रक्रियाओं का उल्लेख करने तथा ग्लोबल ऑडियंस के लिए शहर की शानदार शूटिंग लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए यहां है।

मंडप में बातचीत के दौरान, एएफडीसी प्रबंधन ने भारत के आगामी प्रमुख महोत्सवों के बारे में भी बात की, जिसमें जून 2026 में होने वाला मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 और हर साल 20 से 28 नवंबर तक होने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) शामिल हैं। इन महोत्सव को सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों, सह-निर्माण और बाजार जुड़ाव के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में महत्व दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा मिला।

राजदूत श्री अजीत विनायक गुप्ते ने अपने संबोधन में सिनेमा और रचनात्मकता को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के शक्तिशाली साधनों के रूप में महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ईएफएम में भारत की उपस्थिति न सिर्फ. उसकी पुरानी कहानी कहने (स्टोरीटेलिंग) की परंपरा को दिखाती है, बल्कि ग्लोबल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में उसकी बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है। उन्होंने फि ल्म, संस्कृति और नवाचार में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते तालमेल के बारे में बताया, और ईएफएम जैसे मंच की अहमियत पर जोर दिया ताकि स्थायी क्रिएटिव और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाई जा सके।

भारत मंडप रचनात्मक हितधारकों को एकजुट करता है

एनएफडीसी द्वारा आयोजित भारत मंडप, अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग पॉइंट का काम करता है। पूरे बाजार में, मंडप व्यावसायिक बैठकों, सह-निर्माण संबंधी चचाओं, नेटवर्किंग इंटरैक्शन और उद्योग संवादों की मेजबानी कर रहा है, साथ ही भारत को एक आकर्षक फिल्मांकन गंतव्य-देश और सहयोगी कंटेंट भागीदार के रूप में भी बढ़ावा दे रहा है। यह एक केंद्र-बिंदु की तरह काम करता है जहां फिल्मकार, निमार्ता, टेक्नोलॉजी इनोवेटर, सांस्कृतिक प्रतिनिधि और वैश्विक हितधारक पार्टनरशिप के लिए एकत्रित होते हैं।

इस वर्ष भारत की भागीदारी का एक अहम पहलू ईएफएम इनोवेशन हब में इसकी उपस्थिति है, जहां चार भारतीय टेक स्टार्ट-अप अत्याधुनिक टूल्स और प्लेटफॉर्म प्रस्तुत कर रहे हैं जो इमर्सिव स्टोरीटेलिंग, डिजिटल प्रोडक्शन और मीडिया इकोसिस्टम में उभरती जरूरतों को पूरा करते हैं।

रांची होकर लखनऊ-दिल्ली जाने की राह खुली, नई साप्ताहिक ट्रेन को मिली मंजूरी

रांची। (जीएनएस)।

रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड क्षेत्र के यात्रियों के लिए लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रांची और लखनऊ के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में रेलवे ने अहम कदम उठाते हुए पुरुलिया-आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दे दी है।

यह ट्रेन रांची होकर संचालित होगी और झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आपस में जोड़ेगी। रेलवे ने 14022/14021 पुरुलिया-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को स्वीकृति प्रदान की गई

है। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी, जिसमें आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक गुरुवार और पुरुलिया से प्रत्येक शनिवार को परिचालन प्रस्तावित है।

हालांकि, ट्रेन के नियमित परिचालन की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसे किसी उपयुक्त तिथि से शुरू किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उद्घाटन विशेष सेवा के रूप में भी चलाया जा सकता है।

ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके अलावा वाराणसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, लखनऊ, अयोध्या कैंट, मुरादाबाद और बरेली जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी ठहराव प्रस्तावित है। इससे झारखंड के आदिवासी और पिछड़े इलाकों को उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

रेल मंत्री ने इस संबंध में पलामू के सांसद बीडी राम को पत्र लिखकर ट्रेन की स्वीकृति की जानकारी दी है। रांची से लखनऊ गोमती नगर तक नई ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो अब इस नई सेवा के माध्यम से काफी हद तक पूरी होती नजर आ रही है।

इस रेल सेवा के शुरू होने से व्यापार, रोजगार, शिक्षा और धार्मिक पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

लखनऊः कैफे की आड़ में जिस्फफरोशी, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाकर करवाते थे गंदा काम

(जीएनएस)।

लखनऊ में कैफे की आड़ में चल रहे जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था. एक पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोप है कि लव जिहाद में फंसाकर लड़कियों से गंदा काम करवाया जाता था.

आरोपी हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मंदिर भी जाता था.

लखनऊ में एक कैफे की आड़ में लड़कियों से जबरन जिस्मफरोशी कराई जा रही थी, पीड़िता ने कई गंभीर आरोप लगाए

मुख्य आरोपी राहुल उर्फ कमरू जमाल गरीब लड़कियों को इस धंधे में फंसाने और ब्लैकमेल करने का काम करता था

आरोपी लड़कियों को मंदिर जाकर तिलक लगाकर हिंदू और मुस्लिम लड़कियों को अलग-अलग नामों से फंसाता था

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां कैफे की आड़ में लड़कियों से जबरन जिस्मफरोशी का काम करवाया जाता था. पीड़िता ने आरोपी पर कई अन्य लड़कियों के साथ लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग, जिस्मफरोशी कराने सहित कई गंभीर आरोप लगाए है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हिंदुओं के लिए राहुल, मुस्लिमों के लिए कमरू जमाल

पीड़िता ने बातचीत में बताया कि मामले का मुख्य आरोपी राहुल उर्फ कमरू जमाल है जो गरीब घर की लड़कियों को इस धंधे में उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर धकेल देता था. पीड़िता ने गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता ने बताया कि कमरू जमाल उर्फ राहुल, प्रिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस रैकेट को चलाते हैं. प्रिया महिला का बदला हुआ हिन्दू नाम है.

पीड़िता का कहना है कि ये सभी कई बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई का काम करते थे और जो लड़की नहीं मानती उसे उसके वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देते थे. पीड़िता ने बताया कि हिन्दू लड़कियों को फंसाने के लिए राहुल नाम बताता था और बाकायदा उनके साथ मंदिर जाता था और तिलक लगता था. वहीं मुस्लिम लड़की को फंसाने के लिए वो अपने असली नाम का इस्तेमाल करता था.

ऐसे फंसाते थे लड़कियों को

पीड़िता ने बताया वह 2024 में जॉब की तलाश में लखनऊ आई थी. इस दौरान उसकी मुलाकात राहुल नाम के व्यक्ति से हुई. जिसका असल नाम कमरू जमाल है. पार्लर में जॉब दिलाने के नाम पर साथ ले जाता है जबकि वह मेंस मसाज सेंटर होता है. इस दौरान नशे में कुछ अश्लील वीडियो

बना ली जाती है. उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है. इसके बाद देह व्यापार में धकेल देते हैं. इसके बाद कमर हयात आमिर, कमरू और कई लोग रेप करते हैं. फिर अलग-अलग जिलों में ले जाकर गंदा काम करवाते हैं.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. सीओ बृजनारायण सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. बाकी आरोपों की जांच की जा रही है. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि कमरू लव जिहाद में फंसाकर लड़कियों से गंदा काम करवाता था. लखनऊ के झांगुर केस से भी इसे जोड़कर जांच की जा रही है. वहीं, शिकायत के बाद कैफे का मालिक फरार हो गया है.

लखनऊ के गोमती नगर थाने में लव जिहाद और देह व्यापार के आरोप, पीड़िताओं के समर्थन में पहुंचे हिंदू संगठन

लखनऊ के गोमती नगर थाने में कथित लव जिहाद और देह व्यापार से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर कई पीड़ित युवतियां पहुंचीं. पीड़िताओं ने शिकायत दर्ज न होने का आरोप लगाया. हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अधिवक्ता भी थाने पहुंचे. पीड़िताओं ने बहला-फुसलाकर लाने, ब्लैकमेल और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं.

लखनऊ के गोमती नगर थाने में कथित लव जिहाद, देह व्यापार और सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर कई पीड़ित युवतियां पहुंचीं. पीड़िताओं का आरोप है कि वो पिछले तीन दिनों से थाने के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है. इसे लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी गई.

अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई अधिवक्ता गोमती नगर थाने पहुंचे. संगठनों ने आरोप लगाया कि पीड़िताओं की सुनवाई नहीं हो रही है और पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है.

पीड़ित युवतियों का आरोप है कि अमेठी, बाराबंकी और दिल्ली से लड़कियों को बहला-फुसलाकर लाया गया.